इंडिया पोस्ट बनेगा लाभ केंद्र : सिंधिया

डाक व सॉर्टिंग सहायकों संग मंत्री का संवाद

फ्रंटलाइन कर्मचारियों की समस्याएं सुनी गईं

नई दिल्ली, 3 जुलाई- केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने डाक और सॉर्टिंग सहायकों के साथ एक विस्तृत संवादात्मक सत्र आयोजित किया. संचार मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में बताया कि ये फ्रंटलाइन कार्यकर्ता डाक विभाग की रीढ़ हैं, जो देश भर के सभी 23 डाक सर्किलों का प्रतिनिधित्व करते हैं.

सत्र के दौरान, केंद्रीय मंत्री ने व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक कर्मचारी की बात सुनी, उनके विचारों और प्रतिक्रिया पर उचित ध्यान दिया. उन्होंने प्रतिभागियों को आश्वस्त किया कि उनके सुझावों की सावधानीपूर्वक जांच की जाएगी और भविष्य की नीतिगत निर्णयों तथा परिचालन सुधारों में शामिल किया जाएगा.

डाक सहायक डाकघरों में जनता से सीधे संपर्क स्थापित करने वाले प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं. वे ग्राहक बातचीत का प्रबंधन करते हैं और समय पर सेवा वितरण सुनिश्चित करते हैं, जबकि सॉर्टिंग सहायक रेलवे मेल सेवा, एयर मेल सॉर्टिंग यूनिट और ट्रांजिट मेल कार्यालयों जैसे मेल कार्यालयों में काम करते हैं ताकि मेल और पार्सल की सटीक और समय पर सॉर्टिंग सुनिश्चित हो सके. केंद्रीय मंत्री ने नागरिक-केंद्रित सेवाएं प्रदान करने और प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लागू करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की. उन्होंने ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने और पूरे देश में संचार के सुचारू प्रवाह को बनाए रखने में उनके दैनिक प्रयासों को स्वीकार किया.

केंद्रीय मंत्री ने अपने समर्थन को रेखांकित करते हुए कहा, हम इंडिया पोस्ट को एक अत्याधुनिक संगठन बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं. लेकिन यह परिवर्तन तभी संभव है जब हम सभी मिलकर आगे बढ़ें. मैं इस यात्रा में आपके साथ हूं.

> सत्र के दौरान, केंद्रीय मंत्री ने इंडिया पोस्ट को एक लाभ केंद्र में बदलने की अपनी परिकल्पना को रेखांकित किया. उन्होंने ग्राहकों के लिए वन-स्टॉप समाधान बनने के लिए मेल, पार्सल, अंतर्राष्ट्रीय मेल, बचत बैंक, बीमा और नागरिक-केंद्रित सेवाओं जैसे सभी प्रमुख वर्टिकल में घनिष्ठ समन्वय की आवश्यकता पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि यह समन्वित दृष्टिकोण नवाचार को बढ़ावा देने, दक्षता में सुधार करने और पूरे डाक नेटवर्क में दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने में मदद करेगा.

पठानकोट से चलेगी तीर्थ एक्सप्रेस

28 जुलाई से शुरू होगी 13 दिवसीय यात्रा

तिरुपति, रामेश्वरम, मदुरै समेत प्रमुख स्थल

नई दिल्ली, 3 जुलाई.भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम द्वारा संचालित भारत गौरव स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन दक्षिण भारत यात्रा का शुभारंभ 28 जुलाई 2025 को पठानकोट कैंट स्टेशन से होगा. यह 13 दिवसीय रेल यात्रा श्रद्धालुओं के लिए एक आध्यात्मिक रूप से समृद्ध तीर्थाटन का अवसर प्रदान करेगी.

यह यात्रा भक्तों को दक्षिण भारत के कुछ सबसे प्रतिष्ठित मंदिरों और पवित्र स्थानों पर आशीर्वाद प्राप्त करने, अपनी आध्यात्मिक संबंध को गहरा करने और दिव्य उपस्थिति का अनुभव करने का अवसर देगी.इस विशेष रूप से तैयार की गई तीर्थयात्रा में यात्री तिरुपति, रामेश्वरम, मदुरै, कन्याकुमारी और मल्लिकार्जुन के दर्शन कर सकेंगे. इस दौरे के लिए कई बोर्डिंग और डी-बोर्डिंग पॉइंट उपलब्ध हैं, जिनमें पठानकोट कैंट, जालंधर सिटी, लुधियाना, चंडीगढ़, अंबाला कैंट, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, हजरत निजामुद्दीन, मथुरा, आगरा कैंट और ग्वालियर शामिल हैं.

ट्रेन में विभिन्न श्रेणियों की सीटें उपलब्ध हैं, जिनमें स्लीपर क्लास में 640 सीटें, 3एसी में 70 सीटें और 2एसी में 50 सीटें शामिल हैं. पैकेज में ट्रेन टिकट, सभी भोजन, डबल/ट्रिपल शेयरिंग के आधार पर आरामदायक और स्वच्छ आवास, बसों द्वारा स्थानांतरण और दर्शनीय स्थल, साथ ही ऑनबोर्ड एस्कॉर्ट, हाउसकीपिंग, सुरक्षा और बुनियादी दवाओं के साथ पैरामेडिकल स्टाफ शामिल है.

टाटा पावर ने बनाया सौर ऊर्जा रिकॉर्ड

पहली तिमाही में 752 मेगावाट की बढ़त

112 प्रतिशत साल-दर-साल ग्रोथ हासिल

मुंबई, 03 जुलाई (वार्ता) भारत अक्षय ऊर्जा क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों में से टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में कुल 752 मेगावाट की अक्षय सौर परियोजनायें चालू की हैं.

टाटा पावर कंपनी लिमिटेड (टाटा पावर) ने गुरुवार को जारी एक विज्ञप्ति में कहा कि उसकी अनुषंगी कंपनी टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी का यह एक नया तिमाही रिकार्ड है और एक साल पहले इसी तिमाही में शुरू की गयी 354 मेगावाट की परियोजनाओं की तुलना में 112 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है.

विज्ञप्ति में कहा गया है कि उन्नत इंजीनियरिंग प्रथाओं का लाभ उठाते हुए, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी ने चुनौतीपूर्ण वातावरण में भी लगातार परियोजनायें पूरी की हैं. वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में चालू परियोजाओं के साथ कंपनी की कुल विद्युत आपूर्ति स्तरीय परिचालन क्षमता अब 5600 मेगावाट हो गयी है, जिसमें 4600 मेगावाट सौर और 1000 मेगवाट पवन उर्जा उत्पादन की क्षमता शामिल है.

डालर के मुकाबले रुपया 31 पैसे मजबूत

नयी दिल्ली, 3 जुलाई (वार्ता) अंतर बैंक विदेशी मुद्रा बाजार में गुरुवार को रुपया अमेरिकी डालर के साथ 31 पैसे मजबूत हो कर 85.31 (अनंतिम) रुपये प्रति डालर पर बंद हुआ.

रुपया प्रारंभ में नरमी दिखी लेकिन, ब्रेंट क्रूड की नरमी तथा अन्य प्रमुख एशियायी मुद्राओं के आगे अमेरिकी मुद्रा के नरम पड़ने से रुपये का रुख बदल गया . विदेशी मुद्रा बाजार के कारोबारियों के अनुसार अमेरिका में गैर कृषि क्षेत्र के रोजगार बाजार के आज शाम जारी होने वाले साप्ताहि आंकड़ों से पहले डॉलर इंडेक्स - 96.832 के दायरे स्थिर था. न्यूयार्क जिंस बाजार में ब्रेंट क्रूड करीब 0.333 प्रतिशत नरम होकर 68.83 डालर प्रति बैरल के स्तर पर बोला जा रहा था.

कॉर्पोरेट मुनाफा ने जीडीपी को पछाड़ा

निफ्टी 500 कंपनियों की आमदनी में 6 .8 प्रतिशत उछाल

मिड-स्मॉल कैप फर्मों ने लार्ज कैप को पीछे छोड़ा

नई दिल्ली, 3 जुलाऑई. भारतीय कंपनियों ने पिछले पांच वर्षों में शानदार वित्तीय मजबूती दिखाई है, जिसमें वित्त वर्ष 2020 और वित्त वर्ष 25 के बीच कॉर्पोरेट मुनाफे में देश के सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में लगभग तीन गुना तेजी से वृद्धि हुई है.

आयनिक वेल्थ द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, प्रॉफिट-टू-जीडीपी रेश्यो में शानदार वृद्धि हुई है और यह 6.9 प्रतिशत हो गया है, जो आर्थिक चुनौतियों के बावजूद मजबूत आय प्रदर्शन को दर्शाता है.' इंडिया इंक वित्त वर्ष 25- डिकोडिंग अर्निंग्स ट्रेंड्स एंड पाथ अहेड' शीर्षक वाली रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि वित्त वर्ष 2025 भारतीय कंपनियों के लिए एक मजबूत वर्ष रहा. निफ्टी 500 फर्मों का राजस्व सालाना आधार पर 6.8 प्रतिशत बढ़ा, जबकि ईबीआईटीडीए में 10.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 5.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई.

मिड-कैप और स्मॉल-कैप कंपनियों ने लाभ वृद्धि के मामले में लार्ज-कैप फर्मों को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने क्रमशः 22 प्रतिशत और 17 प्रतिशत पीएटी वृद्धि दर्ज की, जबकि लार्ज कैप के लिए यह केवल 3 प्रतिशत थी.सेक्टर वाइज, बीएफएसआई लाभप्रदता के एक प्रमुख चालक के रूप में उभरे, कोरोना महामारी के बाद से कुल लाभ में इसका हिस्सा लगभग दोगुना हो गया.

बैंकों में एफआरआई सिस्टम लागू होगा

दूरसंचार विभाग ने सिस्टम का किया स्वागत

मोबाइल नंबरों को जोखिम स्तर पर वर्गीकृत करेगा

नई दिल्ली, 3 जुलाई. भारतीय रिजर्व बैंक ने एक महत्वपूर्ण सलाह जारी की, जिसका दूरसंचार विभाग ने स्वागत किया है. इस सलाह में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, लघु वित्त बैंकों, भुगतान बैंकों और सहकारी बैंकों को दूरसंचार विभाग द्वारा विकसित वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक को अपने सिस्टम में एकीकृत करने का निर्देश दिया गया है.

यह कदम साइबर-सक्षम वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने और डिजिटल अर्थव्यवस्था में नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है.मई 2025 में दूरसंचार विभाग की डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा लॉन्च किया गया वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक एक जोखिम-आधारित उपकरण है, जो राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल, दूरसंचार विभाग के चक्षु प्लेटफ़ॉर्म और बैंकों से प्राप्त खुफिया जानकारी के आधार पर मोबाइल नंबरों को मध्यम, उच्च या बहुत उच्च जोखिम के रूप में वर्गीकृत करता है. यह उपकरण सुरक्षित, क्क्षु-आधारित सिस्टम के जरिए बैंकों और दूरसंचार विभाग के डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफ़ॉर्म के बीच वास्तविक समय में डेटा आदान-प्रदान को सक्षम बनाता है.

एफआरआई के एकीकरण से बैंक संदिग्ध लेनदेन को तुरंत अस्वीकार कर सकते हैं, ग्राहकों को सतर्क कर सकते हैं या उच्च जोखिम वाले लेनदेन में देरी जैसे तत्काल निवारक कदम उठा सकते हैं.

> **डिजिटल इंडिया को मजबूती**
> दूरसंचार विभाग ने एफआरआई जैसे तकनीकी समाधानों के माध्यम से बैंकों और वित्तीय संस्थानों का समर्थन करने की प्रतिबद्धता दोहराई है. यह कदम सरकार के डिजिटल इंडिया विज़न के अनुरूप है, जिसका लक्ष्य डिजिटल विश्वास को बढ़ाना, धोखाधड़ी का पता लगाने में सुधार और वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है. यह पहल प्रमुख एजेंसियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देगी और भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को और सुरक्षित बनाएगी.

ईएसआईसी ने एसपीआरईई योजना शुरू की

एसपीआरईई 2025 को मिली निगम की मंजूरी

पंजीकरण 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक

नयी दिल्ली, 02 जुलाई (वार्ता) कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) ने नियोक्ता और कर्मचारियों के पंजीकरण को बढ़ावा देने की योजना - एसपीआरईई 2025 को मंजूरी दे दी है.

एसपीआरईई 2025 का उद्येश्य नियोक्ताओं को अपने कार्यबल को नियमित करने के लिए प्रोत्साहित करना अधिक से अधिक श्रमिक, विशेष रूप से संविदा क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों तक ईएसआई अधिनियम के तहत आवश्यक स्वास्थ्य और सामाजिक लाभों को पहुंचाना है.

श्रम मंत्रालय की बुधवार को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार ईएसआई निगम की शिमला में आयोजित 196वीं बैठक के दौरान संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी. बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय श्रम और रोजगार तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने की.

विज्ञप्ति में कहा गया है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा अनुमोदित नियोक्ता और कर्मचारियों के पंजीकरण को बढ़ावा देने की योजना 2025, ईएसआई अधिनियम के तहत सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करने के उद्देश्य से एक विशेष पहल है. यह योजना पहली जुलाई से लागू मानी जाएगी और 31 दिसंबर तक लागू रहेगी. इसमें अपंजीकृत नियोक्ताओं और संविदा और अस्थायी सहित सभी कर्मचारियों को निरीक्षण या पिछले बकाये की बाध्यता के बिना नामांकन करने का एक बार के लिए अवसर प्रदान किया जा रहा है.

जून में मॉयल का रिकॉर्ड उत्पादन

तिमाही उत्पादन में 6 .8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज

नयी दिल्ली, 03 जुलाई (वार्ता) मैंगनीज अयस्क उत्पादक सरकारी कंपनी मॉयल ने खनन कार्य की अपनी मजबूत वृद्धि दर को जारी रखते हुए जून में 1.68 लाख टन मैंगनीज अयस्क का उत्पादन किया जो उसके उत्पादन का नया मासिक रिकॉर्ड है.

इस वर्ष जून के उत्पादन में सालाना आधार पर दो प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी है.

कंपनी ने गुरुवार को एक विज्ञप्ति में बताया कि चालू वित्त वर्ष 2025-26 के पहले तीन महीनों अप्रैल-जून, 2025 में उसका उत्पादन 5.02 लाख टन रहा. यह कंपनी का अब तक का सर्वश्रेष्ठ तिमाही उत्पादन है और यह पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 6.8 प्रतिशत अधिक है.

समाचार विशेष

बिहार में कांग्रेस ने नियुक्त किए 58 पर्यवेक्षक

संगठन की मजबूती पर रहेगा फोकस

पटना. बिहार में साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है. कांग्रेस मुख्यालय से जारी पर्यवेक्षकों की लिस्ट में रिटायर्ड विंग कमांडर अनुमा आचार्य, मेहंदी, अशोक चांदना, मनोज यादव, नदीम जावेद, शोएब खान, अखिलेश यादव, वीरेंद्र यादव जैसे 58 नेताओं का नाम शामिल है.

2020 बिहार विधानसभा चुनाव में सत्ता चूका महागठबंधन इस बार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता है. पिछले विधानसभा चुनाव में 'महागठबंधन' के सबसे बड़े घटक दल आरजेडी ने 144 सीट पर चुनाव लड़ा था और 75 सीट जीती थी. वहीं कांग्रेस ने 70 सीट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन 19 सीटों पर जीत मिली थी. गठबंधन की दूसरी सहयोगी भाकपा (माले) लिबरेशन ने 19 सीट पर चुनाव लड़ा और 12 सीटें हासिल की थीं. इस चुनाव परिणाम ने बिहार में कांग्रेस के प्रदर्शन पर कई सवाल खड़े कर दिए थे. यही वजह है कि कांग्रेस इस बार मजबूती से चुनाव में मौजूदगी दर्ज कराने की तैयारी में है.

खड़गे द्वारा 58 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के बाद बिहार कांग्रेस ने बधाई दी है. बिहार कांग्रेस ने सोशल मीडिया एक्स पर पर्यवेक्षकों की लिस्ट शेयर करते हुए लिखा कि माननीय कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खरगे जी ने बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए निम्नलिखित पार्टी पदाधिकारियों को एआईसीसी पर्यवेक्षकों के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को तत्काल प्रभाव से मंजूरी दे दी है. आप सभी सम्मानित साथियों को बिहार कांग्रेस परिवार की ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं.

> **चुनाव में टीम के सदस्य निभाएंगे अहम भूमिका**
> बिहार में 'सुपर 58' की नियुक्ति में कांग्रेस ने समीकरणों को भी ध्यान में रखा है. इस लिस्ट में सभी वर्गों के नेताओं को शामिल किया गया है. इसमें ओबीसी, एससी, अल्पसंख्यकों के साथ ही सवर्ण जाति के नेताओं को जगह दी गई है. इस टीम को लेकर लेकर माना जा रहा है कि विधानसभा क्षेत्रों के अनुसार इन लोगों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी. ये सभी 58 पर्यवेक्षक स्थानीय कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे, इसके साथ ही जमीनी हकीकत का आकलन करेंगे. इसके साथ ही संगठन को विधानसभा से लेकर बूथ स्तर तक मजबूत करेंगे. अब देखना होगा कि यह टीम पार्टी के लिए कितना और क्या कुछ काम कर पाती है.

राजनीतिक राह बदलेंगे बृजभूषण सिंह?

बस्ती. कथावाचकों की पिटाई का मुद्दा इस समय यूपी में तूल पकड़े हुए है. इससे अखिलेश यादव बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं. समाजवादी पार्टी अध्यक्ष ने बागेश्वर धाम वाले धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि वो एक कथा के लिए 50 लाख रुपये लेते हैं. भाजपा इस बयान के बाद अखिलेश यादव को सनातन विरोधी बता रही है.

इस बीच पार्टी के बाहुबली नेता उनके समर्थन में उतर आए हैं, जिससे सब हैरान हैं. आखिर इसके पीछे क्या राजनीति है और बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रज भूषण शरण सिंह ने तो अखिलेश यादव को सच्चा हिंदू बताया है. बस्ती में एक स्वागत समारोह के दौरान बृजभूषण सिंह के एक बयान से यूपी की राजनीति में हलचल ला दिया है. उनके बयान के बाद से कयासों का बाजार गर्म हो गया है. राजनीतिक गलियारे में चर्चा है कि क्या बृजभूषण सिंह अपनी राजनीतिक राह बदलने के लिए कोई बड़ी चाल चलने वाले हैं? बृजभूषण शरण सिंह ने अपने बयान में न सिर्फ अखिलेश यादव को सीधे तौर पर कृष्ण का वंशज बताया, साथ ही उनके द्वारा बनवाए गए एक मंदिर की भी खुलकर तारीफ की.

> **अखिलेश को बताया कृष्ण का वंशज**
> बृजभूषण सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव भगवान कृष्ण के वंशज हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है. बीजेपी नेता ने आगे कहा कि अखिलेश यादव ने बहुत बढ़िया मंदिर बनवाया है. बृजभूषण शरण सिंह का ये बयान ऐसे वक्त में आया है, जब देश में धार्मिक तथा आध्यात्मिक मुद्दे, विशेष तौर पर मंदिर निर्माण और उससे जुड़ी राजनीति, चर्चा का केंद्र बनी हुई है.

गठबंधन सरकार मंजूर नहीं अन्ना डीएमके को

चेन्नई. तमिलनाडु में अन्ना डीएमके और भाजपा गठबंधन के करार की स्याही सूखी नहीं है और विवाद शुरू हो गया है. असल में अन्ना डीएमके की ओर से बहुत पहले से कहा जा रहा है कि राज्य में राज्य में अगर सरकार बनाने की स्थिति बनती है या उसको बहुमत मिलता है तो सरकार सिर्फ उसकी बनेगी, वह एनडीए की सरकार नहीं होगी. पार्टी की ओर से यह भी कहा जा चुका है कि भाजपा को सरकार में नहीं शामिल किया जाएगा. फिर भी पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि अगले साल के विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत होगी और राज्य में एनडीए की सरकार बनेगी.

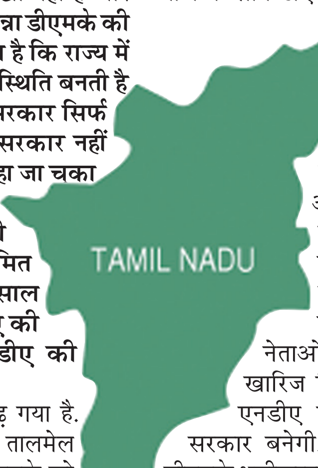

इस बात को लेकर विवाद बढ़ गया है. विवाद इसलिए बढ़ा है कि तमाम तालमेल और गठबंधन के बावजूद अन्ना डीएमके को लग रहा है कि एनडीए की सरकार बनने का हल्ला बना तो पूरे गठबंधन को नुकसान होगा. तभी पार्टी के लोग डीएमके बनाम अन्ना डीएमके चुनाव बनाना चाहते हैं. अगर एनडीए की सरकार बनाने की बात कही जाएगी तो डीएमके को यह कहने का मौका मिलेगा कि भाजपा की सरकार बन रही है तो भाजपा और आरएसएस का एजेंडा लागू होगा. इसमें भाषा से लेकर द्रविड संस्कृति और सनातन को लेकर चल रही सारी बहस फिर से शुरू हो जाएगी. तभी अन्ना डीएमके नेताओं ने अमित शाह के बयान को खारिज किया और कहा कि राज्य में एनडीए की नहीं अन्ना डीएमके की सरकार बनेगी. कहा जा रहा है कि अन्ना डीएमके ध्रुवीकरण का कोई मुद्दा डीएमके को नहीं देना चाहती है.

विशेष | जलवा दिखाने की तैयारी में राव इंद्रजीत

द . हरियाणा के साथ अब चंडीगढ़ पर भी नजर

चंडीगढ़. दक्षिण हरियाणा की राजनीति में मजबूत पकड़ रखने वाले केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह अब चंडीगढ़ में भी सक्रिय दिखाई देंगे. राव इंद्रजीत की बेटी आरती सिंह राव हरियाणा की भाजपा सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं. चंडीगढ़ में राव की राजनीतिक गतिविधियां अपनी बेटी के सरकारी आवास से संचालित होंगी.

पिछले दिनों उन्होंने चंडीगढ़ में अपनी बेटी के आवास पर दक्षिण हरियाणा के एक दर्जन विधायकों के साथ रात्रि भोज कर इसकी शुरुआत कर दी है. राव की योजना ऐसे भोज निरंतर करते रहने की है, ताकि दक्षिण हरियाणा से बाहर निकलकर राजधानी चंडीगढ़ की राजनीति में हस्तक्षेप बढ़ाया जा सके.

चंडीगढ़ में राव इंद्रजीत के इस पहले रात्रिभोज में दक्षिण हरियाणा के 11 भाजपा विधायकों के साथ नांगल चौधरी की कांग्रेस विधायक मंजू चौधरी भी शामिल हुईं. भाजपा ने नांगल चौधरी से डॉ. अभय सिंह यादव को टिकट दिया था, लेकिन राव इंद्रजीत उन्हें टिकट दिए जाने के हक में नहीं थे. हरियाणा सरकार में सिंचाई राज्य मंत्री रह चुके अभय सिंह यादव के प्रति राव की नाराजगी का फायदा कांग्रेस की मंजू चौधरी को मिला और वह चुनाव जीत गई. चुनाव में राव द्वारा मदद करने की बात मंजू चौधरी ने स्वयं स्वीकार की है. राव के इस रात्रि भोज में उनकी बेटी आरती के साथ चरखी दादरी के विधायक सुनील सांगवान, बाढ़डा के विधायक उम्मेद पातुवास, महेंद्रगढ़ के विधायक कंवर सिंह, नारनौल के विधायक ओमप्रकाश यादव और पटौदी की विधायक बिमला चौधरी शामिल हुए. रेवाड़ी के भाजपा विधायक लक्ष्मण यादव, कोसली के विधायक अनिल यादव, बावल के विधायक डॉ. कृष्ण कुमार रंगा, सोहना के विधायक तेजपाल तंवर और गुरुग्राम के विधायक मुकेश शर्मा भी राव इंद्रजीत के रात्रिभोज के साक्षी बने.

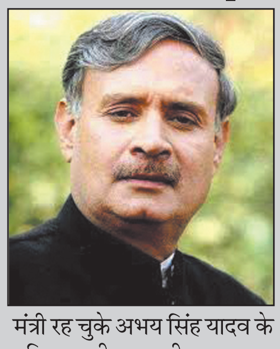

> **हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने में अहीरवाल बेल्ट की अहम भूमिका**
> दक्षिण हरियाणा में साल 2024 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 17 सीटें जीतीं थी, जबकि कांग्रेस की झोली में छह सीट आईं थी. ऐसे में भाजपा की लगातार तीसरी बार सरकार बनने में दक्षिण हरियाणा खासकर अहीरवाल बेल्ट की अहम भूमिका रही है. राव इंद्रजीत गुरुग्राम से सांसद हैं और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की कैबिनेट में राज्य मंत्री हैं. राव जब कांग्रेस में रहे और उसके बाद भाजपा की राजनीति करने लगे, तब-तब उनकी मुख्यमंत्रियों से कभी नहीं बनीं.